5 हजार करोड़ रुपए का हो सकता है अनुपूरक बजट

21 को विधानसभा में पेश हो सकता है अनुपूरक

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 18 जुलाई. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वित्त विभाग ने प्रथम अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी कर ली है. मिले संकेतों के मुताबिक अनुपूरक बजट बेहद सीमित होगा और यह लगभग 5 हजार करोड़ रुपए के आसपास रहेगा. इस अनुपूरक में सबसे अधिक राशि ऊर्जा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण और नगरीय विकास जैसे बड़े विभागों के लिए इंतजाम किया जा सकता है.

मप्र विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा. सत्र के अगले दिन 21 जुलाई को ही सदन में प्रथम अनुपूरक बजट पेश होने की संभावना है. उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इसे सदन में पेश करेंगे. अनुपूरक में सबसे अधिक राशि ऊर्जा विभाग के लिए प्रावधान किए जाने की संभावना है. विभाग ने सबसे अधिक राशि की डिमांड की है, विशेष रूप से किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी के लिए बिजली कंपनियों को अग्रिम राशि का भुगतान किया जाना है, जिसके लिए विभाग को बड़ी राशि दी जा सकती है. मिले संकेतों के मुताबिक ये राशि 1500 करोड़ रुपए तक हो सकती है. इसके अलावा नगरीय विकास एवं आवास के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए तक राशि का इंतजाम किया जा सकता है, इधर लोक निर्माण विभाग ने भी एक हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि की डिमांड की है, ऐसे में विभाग के लिए भी भारी-भरकम राशि का इंतजाम किया जा सकता है. यह इसलिए कि बारिश के सीजन में सड़कें जर्जर हो जाती है और फिर बारिश के बाद सड़कों की मरम्मत और निर्माण का काम तेजी से शुरू किया जाता है, इसलिए पहले ही इस मद में अग्रिम राशि का प्रावधान किया जा सकता है.

इधर प्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत प्रदेश में बड़े स्तर पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भवनों का निर्माण हो रहा है. ये काम लगातार बिना परेशानी के चलते रहे, इसके लिए भी प्रथम अनुपूरक में 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जा सकता है.

किसी भी विभाग को नए वाहन, साज-सज्जा के लिए नहीं मिलेगी राशि

वित्त विभाग ने अनुपूरक बजट के लिए पहले ही सख्त वित्तीय अनुशासन लागू कर दिया था, विभागों से प्रस्ताव आमंत्रित करने से पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि कोई भी विभाग नए वाहन या फिर कार्यालयों की साज-सज्जा सहित ऐसे कार्य जो कि बेहद आवश्यक श्रेणी में नहीं आते, उन सभी के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने पर रोक लगा दी थी. इतना ही नहीं विभागों को यह भी निर्देश दिए थे कि यदि किसी विभाग को अनुपूरक में राशि की आवश्यकता है, तो फिर उनको इसकी उपयोगिता साबित करना होगा. इसलिए विभागों ने बेहद सीमित संख्या में राशि का प्रावधान करने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है, जिसके चलते अनुपूरक बजट का आकार अब सीमित होने लगा है.

मौसम : राजधानी भोपाल में छाये रहे मेघ

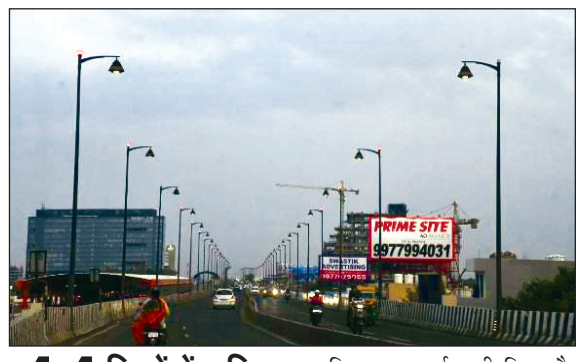

44 जिलों में बारिश का अलर्ट

भोपाल, 18 जुलाई . मध्यप्रदेश में करीब नौ दिन की सुस्ती के बाद मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को प्रदेश के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि डिंडोरी और उमरिया जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है. वही राजधानी में दोपहर के बाद बादल छाए रहे और धीमें - धीमें बारिश हो रही है . 19 जुलाई से नया मौसमी तंत्र पूरी तरह सक्रिय होने के साथ प्रदेश में तेज बारिश का नया दौर शुरू होगा.

बदल रहा मानसून, बदल रहा मौसम का मिजाज

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पिछले एक दशक के रिकॉर्ड बताते हैं कि मध्यप्रदेश में मानसून का स्वरूप लगातार बदल रहा है . 2016 से 2025 के बीच कई वर्ष सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा वाले रहे, लेकिन बारिश का वितरण पहले की तुलना में अधिक असमान होता गया . कई जिलों में कम समय में अत्यधिक बारिश दर्ज हुई, जबकि दूसरे हिस्सों में लंबे सूखे अंतराल बने रहे . 2019 और 2020 में प्रदेश में अच्छी वर्षा के बावजूद कई स्थानों पर बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी .

देशभर में आयुर्वेद की 10 हजार सीटें कम होने की आशंका

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 18 जुलाई. जल्द ही नया संकट खड़ा हो सकता है. एक तरफ जहां प्रदेश में एमबीबीएस की सीटों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस सत्र में आयुर्वेद यानी बीएएमएस की दस हजार से भी ज्यादा सीटें कम होने की आशंका जताई जा रही है.

जिसका सीधा असर प्रदेश के सैकड़ों आयुष छात्रों पर पड़ सकता है. बता दें विशेषज्ञों के अनुसार इन सीटों में संभावित कटौती का कारण भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा कॉलेजों में तय मापदंडों का कड़ाई से पालन कराना है. बता दें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित देशभर में लगभग 625 आयुर्वेद कॉलेज संचालित हैं, जिनमें कुल सीटों की संख्या करीब 40 हजार है.

सूत्रों के अनुसार, मप्र और अन्य राज्यों के कई कॉलेजों में टीचिंग व नॉन-टीचिंग स्टाफ की बायोमेट्रिक अटेंडेंस में कमी, ओपीडी और आईपीडी में मरीजों की कम संख्या, आधुनिक उपकरणों का अभाव और ऑन-पेपर फैकल्टी जैसी गंभीर लापरवाहियां सामने आई हैं. कई कॉलेज तो आयोग द्वारा किए जाने वाले औचक निरीक्षण से भी कतरा रहे हैं. इन कमियों के चलते सत्र 2026-27 में बीएएमएस की कुल सीटों में लगभग 20 फीसदी की कटौती की जा सकती है.

अवैध हथियारों के जिला गिरोह का भंडाफोड़

दमोह. पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगि (भापुसे) के निर्देशन में हटा पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले अंतर जिला गिरोह का शनिवार को पर्दाफाश किया है. शहर के जबलपुर नाका स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी आनंद कलादगि (भापुसे) ने पूरी कार्रवाई का खुलासा किया. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह कार्रवाई एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया और एसडीओपी हटा के.पी. सिंह के नेतृत्व में गठित अनुभाग स्तरीय टीम द्वारा अंजाम दी गई. टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया. पुलिस ने मौके से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

मंत्रालय के गलियारे से

बाल-बाल बचे साहब

कन्हैया लोधी

पिछले दिनों सरकार में बहुत कुछ घटा. कुछ ऐसा कि एक मंत्रीजी को लेने के देने पड़ गए. मंत्रीजी को लेकर जो खबरें निकलकर आ रही है, उसके मुताबिक वे विभाग में पूरे इत्मीनान के मूड में थे, उन्हें अंदेशा ही नहीं था, कि कुछ ऐसा होगा. उनके आसपास जो स्टॉफ तैनात है, उसने उन्हें पूरा भरोसा दिला रखा था कि वे सरकार के सबसे तेज काम करने वाले मंत्री है. भला उनका कोई क्या ही कर लेगा, लेकिन वे भूल गए कि ये महकमा सरकार की टॉप प्रायोरिटी में है, जिस पर नजर दिल्ली की भी है. बस फिर क्या था, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के बजाय केवल मंत्री बनाए रखा गया. लेकिन बताया ये जा रहा है कि विभाग के बड़े साहब पर भी सरकार की नजर पड़ी थी, लेकिन वे बाल-बाल बच गए. रिटायरमेंट की दहलीज के चलते वे बच निकले.

शिकायत के इंतजार में साहब

मंत्रालय की चौथी मंजिल के एक अफसर अपने नकचढ़े अंदाज के चलते मंत्रालय में सुर्खिया बटोर रहे हैं . दरअसल उन्हें मैदान से हटाकर मंत्रालय की चौथी मंजिल में पदस्थ कर दिया गया है . जहां उनकी पोस्टिंग की गई है, वहां काम की कमी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी डाकिये जैसी ही है . अब वे गुस्सा मातहतों पर निकाल रहे हैं, जब भी कोई मिले तो उनका रवैया चिढ़चिढ़े अंदाज में ही रहता है, इसलिए उनसे मिलने वाले सीमित है . वैसे चर्चा ये भी है कि वे इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनकी शिकायत हो और उन्हें वहां से हटाकर कोई दूसरी जिम्मेदारी मिले .

ये जुगलबंदी क्या रंग लाएगी

राजनीति अपनी जगह है और व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह . प्रदेश की राजनीति में एक-दूसरे के धूर विरोधी बड़े राजनीतिक दल के दो बड़े नेता अनायास ही सफर में टकरा गए . बस फिर क्या था, दोनों ही नेताओं के बीच राजनीति और राजनीति से इतर दोनों ही तरह की बातें होती रही . सफर लंबा था और दोनों की मंजिल एक ही थी, लिहाजा इस जुगलबंदी के मायने तलाशे जा रहे हैं . हांलाकि इस मुलाकात को सद्भावना के साथ ही राजनीतिक सुचिता से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि राजनीति में आज के दौर की सबसे ज्यादा जरुरत है .

कमीशन का सिस्टम

सरकारी विभागों में काम कैसे होता है, वैसे तो ज्यादा बताने की जरुरत नहीं है, मजाल है कि बिना रिश्वत के काम आगे बढ़ जाए, यदि मामला मैदानी अमले का हो तो फिर कहने ही क्या . पिछले दिनों एक बड़े महकमे के इंजीनियर साहब ने रिश्वत के मामले में ऐसी चुनौती दी, कि उनको चुनौती देने कोई सामने नहीं आ सका . आखिर उन्होंने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी था . उनका ये पोल खोल अंदाज सोशल मीडिया में खुब सुर्खियों में छाया रहा . वैसे बता दें कि जिस विभाग के इंजीनियर है, उस महकमे के मंत्रीजी बड़े सात्विक होने का दावा करने में पीछे नहीं रहते .

परीक्षा केंद्र चयन में व्यवस्था करें बहाल : दिग्विजय

विशेष संवाददात

भोपाल, 18 जुलाई . मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर नीट पीजी-2026 परीक्षा के लिए शहर-आधारित परीक्षा केंद्र चयन व्यवस्था को पुनः लागू करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रणाली अभ्यर्थियों पर अनावश्यक आर्थिक और मानसिक बोझ डाल रही है.

अपने पत्र में दिग्विजय सिंह ने कहा कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज़ (एनबीईएमएस) ने पहले की व्यवस्था, जिसमें अभ्यर्थी अपनी पसंद के परीक्षा शहर चुन सकते थे, को समाप्त कर केवल तीन राज्यों का विकल्प चुनने की व्यवस्था लागू कर दी है. उनके अनुसार, पहले अभ्यर्थियों को सुविधा के अनुरूप शहर चुनने का अवसर मिलता था. उन्होंने आशंका जताई कि नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित हो सकते हैं, जिससे यात्रा और ठहरने का खर्च बढ़ेगा तथा मानसिक तनाव भी बढ़ेगा.

सोलर प्रोजेक्ट की फाइल पर रिश्वत का करंट

इंदौर. सोलर पैनल की फाइल आगे बढ़ाने के बदले रिश्वत मांगने के मामले में लोकायुक्त ने शनिवार को बिजली कंपनी के सुखलिया जोन कार्यालय में कार्रवाई करते हुए एक कनिष्ठ यंत्री को 40 हजार रुपए लेते रंगे हाथ पकड़ लिया. आरोपी ने काम करने के एवज में 80 हजार रुपए की मांग की थी. अंबे नगर स्थित जीआर 7 होटल भवन पर सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया चल रही थी. इसी दौरान संबंधित फाइल आगे बढ़ाने के लिए कनिष्ठ यंत्री नमेश कुमार भोंडेकर ने शिकायतकर्ता से 80 हजार रुपए की रिश्वत मांगी. शिकायतकर्ता ने 17 जुलाई को लोकायुक्त कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत की.

शुक्ल ने जैन संत मुनियों से लिया आशीर्वाद

उप मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल

रीवा 18 जुलाई 2026. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए . उप मुख्यमंत्री ने आचार्य विजयसागर महाराज के परम शिष्य आचार्य समयसागर महाराज तथा अतुल सागर महाराज के भव्य मंगल प्रवेश में शामिल हुए.

उप मुख्यमंत्री ने जैन संत मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त किया. इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में संतो का सान्निध्य समाज को सदाचार सयम और कल्याण का मार्ग दिखाता है. ऐसे पावन अवसर अध्यात्मिक चेतना और सामाजिक संरचना को मजबूत करते हैं. उप मुख्यमंत्री ने विजय मिश्रा के निवास स्थल पर अखण्ड रामचरित्र मानस में भागीदारी निभाई. इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने विनायक प्रसाद तिवारी के सगरा स्थित निवास पहुंचकर उनकी दिवंगत माता को श्रद्धाजलि अर्पित की तथा परिवारजनों को सांत्वना दी. उप मुख्यमंत्री ने इसके बाद कुबेर तालाब में आयोजित कार्यक्रम में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष स्व. राघवचरण मिश्र को श्रद्धासुमन अर्पित किये. उप मुख्यमंत्री ने संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर कमलेश सचदेवा की बहन की स्वास्थ्य की जानकारी ली. उप मुख्यमंत्री ने मिनर्वा अस्पताल जाकर वहां उपचार करा रहे अमित कोहली के पिता के स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उनके शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना की.

भोपाल-देवास टोल कंपनी को 11 करोड़ लौटाने का आदेश

जबलपुर, 18 जुलाई. हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने भोपाल-देवास फोरलेन पर फास्टैग के जरिए तीन एक्सेल बसों से अधिक टोल वसूली को अवैध ठहराते हुए टोल कंपनी को करीब 11 करोड़ रुपये प्रभावित वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को लौटाने के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट ने मेसर्स देवास-भोपाल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका खारिज करते हुए एमपी रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन (एमपीआरडीसी) के 21 मई 2025 के आदेश को बरकरार रखा. कंपनी पर 25 हजार रुपये कास्ट लगाई गई है, जिसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करना होगा. कंपनी का तर्क था कि फास्टैग सिस्टम में तीन एक्सल बसों को तकनीकी रूप से मल्टी एक्सल वाहन की श्रेणी में दर्ज किए जाने के कारण अधिक टोल स्वतः कटता रहा, इसलिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती. हाईकोर्ट ने यह दलील खारिज करते हुए कहा कि फास्टैग केवल भुगतान का माध्यम है, टोल की दर या वाहन की श्रेणी तय करने का अधिकार उसे नहीं है.

रेलवे परिसर में अवैध वेंडिंग के खिलाफ आरपीएफ की सख्त कार्रवाई, 2,909 वेंडरों पर शिकंजा

भोपाल , 18 जुलाई. रेलवे परिसर में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल ने इटारसी स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में अवैध वेंडिंग के खिलाफ सघन अभियान तेज कर दिया है. वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त डॉ. अभिषेक के मार्गदर्शन में चल रहे अभियान में सीसीटीवी, स्टैंड-अलोन सर्विलांस कैमरे, बॉडी वॉर्न कैमरे और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर निगरानी मजबूत की गई है. आरपीएफ द्वारा स्टेशन, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, कोचिंग यार्ड तथा संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है.

6 हजार का लालच देकर 6 लाख के जेवरात ले उड़ा बुलेट सवार

रीवा नवभारत

मउगंज. जिले के लौर थाना क्षेत्र में ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक बुलेट सवार युवक ने 6 हजार रुपये प्रतिमाह दिलाने का झांसा देकर 72 वर्षीय वृद्ध महिला से कथित तौर पर लगभग 6 लाख रुपये मूल्य के सोने के जेवरात ठग लिए.

पीड़ित वृद्ध दंपति ने थाना लौर पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है. शिकायत के अनुसार, 17 जुलाई 2026 को ग्राम इटहा (थाना लौर) निवासी वृद्ध केदार प्रसाद नामदेव अपने घर के बाहर बैठे थे. इसी दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल से युवक वहां पहुंचा और बातचीत के दौरान स्वयं को सरकार की ओर सर्वे कर्मचारी बताते हुए विश्वास में ले लिया. उसने वृद्ध को 6 हजार रुपये प्रति माह दिलाने का लालच दिया और कहा कि अपना आधार दे पंजीयन करना है फिर बोला घर में टीवी, कूलर, पंखा, सायकल या गाड़ी जो हो बताए फिर कहा जो भी सोना चांदी के जेवर हो उसकी गिनती कर बैग या किसी थैले में लाए सभी दर्ज कर दे और पंजीयन शुल्क 5000/ दे जो बाद में रुपये और जेवर दोनों वापस मिल जाएंगे.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14